• शर्मनाक...

महासचिव पर लगा 4 साल का बैन

मंडी : हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के शोषण मामले में प्रदेश फुटबाल संघ के प्रदेश महासचिव पर गाज गिरी है। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के शोषण के आरोप में हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव दीपक शर्मा पर चार साल का प्रतिबंध लगा है।

महिला खिलाड़ियों का शोषण करने पर अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने हिमाचल प्रदेश फुटबाल संघ के प्रदेश महासचिव दीपक शर्मा पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया हैज्र यह प्रतिबंध निलंबित किए जाने की तारीख से आगामी चार साल के लिए है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अनुशासन समिति ने दीपक शर्मा पर यह कार्रवाई की है।

हिमाचल फुटबाल संघ के प्रदेश महासचिव पर लगा 4 साल का बैन-बता दें कि दीपक शर्मा पर कुछ महीने पहले महिला फुटबाल खिलाड़ियों ने छेड़छाड़ और शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद दीपक शर्मा को निलंबित कर दिया गया था। अब इस सारे मामले की जांच के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अनुशासन समिति

के अध्यक्ष वैभव गाग्गर ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया।

इस बारे में जारी पत्र में कहा गया है कि फेडरेशन के संविधान की धारा 51 के तहत हुई जांच में आरोप सही साबित हुए हैं। ऐसे में धारा 18 के तहत अनुशासन समिति ने कार्रवाई करते हुए दीपक शर्मा पर चार साल के लिए फुटबॉल खेल की हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। यह प्रतिबंध उनको जिस दिन निलंबित किया गया था, उस तारीख से जारी होगा।

फेडरेशन के इस फैसले का स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश फुटबाल वेल्फेयर एसोसिएशन ने कहा कि दीपक शर्मा के महासचिव रहते हुए प्रदेश फुटबाल संघ में हुई गड़बड़ियों की भी जांच की भी मांग उठाई है।

• संपादकीय...

विश्व पेपर बैग दिवस

प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा हैं। वे सैकड़ों साल तक टिके रह सकते हैं और जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक बैग जानवरों के लिए भी खतरनाक होते हैं, जो उन्हें खा सकते हैं या उनमें फंस सकते हैं। दूसरी ओर पेपर बैग, पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। वे लकड़ी से बने होते हैं, जो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेपर बैग भी आसानी से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे प्राकृतिक रूप से टूट जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पेपर बैग दिवस मनाने के पीछे के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका संबंध 19वीं शताब्दी से हो सकती है, जब साल 1852 में फ्रांसिस वॉले नामक एक अमेरिकी ने पहला पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया था। इससे पहले लोग सामान कैरी करने के लिए कपड़े, चमड़े और लकड़ी के बक्से का इस्तेमाल करते थे। वॉले के इस आविष्कार ने सामान ढोने के तरीके में क्रांति ला दी और यह पेपर बैग काफी प्रचलित हो गया। हालांकि, प्लास्टिक बैग का आगाज 20वीं सदी के मध्य में हुआ था, जो कि सस्ता, मजबूत और टिकाऊ भी रहा। इसी के कारण पेपर बैग का प्रयोग कम हुआ और प्लास्टिक बैग दुनियाभर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि यह आम बन गया। विश्व पेपर बैग दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों से बचाना और उन्हें इसके बारे में जागरूक करना है। साथ ही, इस खास दिन पर्यावरण के बिगड़ते हालातों और उसकी रक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाने का काम करता है। यही नहीं, इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे एक वजह दुनिया को प्रदूषण से बचाना और लोगों को हेल्दी लाइफ देना भी है। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों को प्लास्टिक बैग के खतरों के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करें।आप चाहें तो डीआईवाई पेपर बैग क्राफ्ट के जरिए पेपर बैग दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी सोसायटी या स्कूलों में पेपर बैग के फायदे के बारे में बताएं।

■ **अनल पत्रवाल**
संपादक, हिमाचल अभी अभी

हिमाचल को मिला नया टारगेट

नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी व हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव आईएएस राकेश कंवर व अन्य अधिकारियों की बैठक हुई।

इसमें हिमाचल को ये लक्ष्य दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को तीसरी टर्म में 100 दिन का रोडमैप पेश करने के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्रियों का अपने विभागों में 100 दिन का क्या एजेंडा व रोडमैप है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी सभी से रिपोर्ट लेंगे...

● पंकज/शिमला

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के समक्ष एक टारगेट रखा गया है। ये टारगेट सरकारी स्कूलों में बारहवीं तक शत-प्रतिशत एनरोलमेंट का है। इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव की बैठक में टारगेट पर चर्चा हुई।

हालांकि हिमाचल में सरकारी स्कूलों में बारहवीं तक छात्रों की एनरोलमेंट का रिकॉर्ड करीब 95 प्रतिशत है, लेकिन इसे शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी व हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव आईएएस राकेश कंवर व अन्य अधिकारियों की बैठक हुई।

इसमें हिमाचल को ये लक्ष्य दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को तीसरी टर्म में 100 दिन का रोडमैप पेश करने के लिए कहा है। कैबिनेट मंत्रियों का अपने विभागों में 100 दिन का क्या एजेंडा व रोडमैप है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी सभी से रिपोर्ट लेंगे।

इसी के तहत अन्य मंत्रियों के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी राज्य के शिक्षा विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से बैठकें कर रहे हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि सभी राज्यों में बारहवीं तक शत-प्रतिशत एनरोलमेंट का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। शत-प्रतिशत एनरोलमेंट से तात्पर्य ये है कि जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन ले, वो बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी करके ही स्कूल से निकले।

इससे ड्रॉप आउट की समस्या दूर होगी। शत-प्रतिशत एनरोलमेंट के रास्ते में जो बाधाएं हों, उन्हें राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर दूर करें। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं। यहां हर जिला की अपनी-अपनी दिक्कतें हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने से कई बार बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कहीं, अभाव व गरीबी के कारण अभिभावक बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते। कई जगह शिक्षकों की कमी कारण होता है। ऐसे में सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास की जरूरत है। कई जगह कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्कूलों की संख्या पर्याप्त से अधिक है। ऐसे में स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है।

शिक्षकों के युक्तिकरण की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आईटी

❖ **केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव की बैठक**

लैब, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेज, बेहतर फर्नीचर आदि की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये भी चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन में आधारभूत गणित को भी शामिल किया जाए। कई बार ये देखने में आया है कि जिन सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं हैं। वहां के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी नहीं है। ऐसा नियम लागू किया गया था। इससे भी एनरोलमेंट प्रभावित होती है। अब नए निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक न हों, वहां के बच्चों को भी स्कूल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। उनके साथ स्कूल टूर्नामेंट में अन्य शिक्षक जाएंगे. इससे भी एनरोलमेंट पर सकारात्मक असर होगा।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर के अनुसार, हिमाचल में शिक्षण व्यवस्था व ढांचा अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। एनरोलमेंट की भी अन्य राज्यों के मुकाबले खास समस्या नहीं है। अलबत्ता जिन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है, वहां काम किया जाएगा।

ये है हिमाचल का शिक्षा ढांचा

हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 10370 है। इसके अलावा मिडिल स्कूल 1850, हाई स्कूल 960 व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 1984 है। छोटे पहाड़ी राज्य में 70 लाख की आबादी के लिए ये शैक्षणिक ढांचा काफी बेहतर है। राज्य में सरकारी सेक्टर में डिग्री कॉलेजों की संख्या 148 है। राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज ये आंकड़े दिसंबर 2023 तक हैं।

राज्य में प्राइमरी शिक्षा के लिए कुल दस स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। इसी तरह मिडिल व हाई स्कूल के छात्रों के लिए राज्य व केंद्र स्तर पर प्रायोजित स्कॉलरशिप योजनाओं की संख्या 14 है। हिमाचल में राज्य सरकार नौवीं व दसवीं कक्षा के छात्रों को निशुल्क किताबें प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 1,41,956 छात्र-छात्राओं को लाभ मिला। शिक्षा सचिव राकेश कंवर का कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

• एचपीयू...

सवालों के घेरे में भर्तियां

शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई है। हाई कोर्ट द्वारा दो प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द किया गया है जिसके बाद छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व वीसी सिकंदर कुमार पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं, जबकि यह शिक्षक अपनी योग्यता भी पुरी नहीं करते हैं। एसएफआई ने लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती को नियमों के विरूद्ध करार दिया है और न्यायिक जांच की मांग की है। एसएफआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए सीटिंग न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग बनाने की मांग की है और तत्कालीन वीसी डॉ. सिकंदर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है वह इन भर्तियों की जांच करवाये। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट में जन हित याचिका दायर करेगी और सड़क से लेकर विधान सभा घेराव कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

• क्षेत्र का निरीक्षण...

■ ***शिमला : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के निकट भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को मरम्मत कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए, ताकि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सर्कुलर सड़क शिमला शहर की जीवन रेखा है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने और आपातकालीन स्थिति में तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।***